शुगर एक्सपोर्ट बढ़ने से किसानों को भुगतान में होगी आसानी

मिलों ने अब तक 20 लाख टन निर्यात का सौदा किया, इससे मौजूदा साल के लिए तय 60 लाख टन का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीदें बढ़ीं

[ऋतुराज तिवारी | नई दिल्ली]

शुगर एक्सपोर्ट में आई हालिया तेजी से मिल मालिकों को किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। सरकार मिलर्स को 10,448 रुपये प्रति टन की सब्सिडी देती है, जो बकाये के सेटलमेंट के लिए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, उतनी ही तेजी से किसानों को भुगतान मिलेगा। मिलों ने अब तक 20 लाख टन चीनी निर्यात करने का सौदा किया है। इससे मौजूदा साल के लिए तय 60 लाख टन निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैश्विक बाजार में चीनी की कीमत 300-350 डॉलर प्रति टन है, जो भारतीय निर्यात के लिए काफी फायदेमंद होगी।'

सरकार मिलर्स को ₹10,448 प्रति टन की सब्सिडी देती है, जो बकाये के सेटलमेंट के लिए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है

इस साल अक्टूबर से शुरू नए चीनी सत्र में गन्ने पर देनदारी करीब 6,000 करोड़ रुपये थी। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश के किसानों का है।

नए सत्र के पेराई शुरू होने के साथ बकाया फिर बढ़ने लगा है। चीनी संगठन इस्मा के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने बताया, 'वैश्विक बाजार में मांग काफी मजबूत है। जानकारों का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट भारत से 30 से 35 लाख टन चीनी खरीद सकता है। इसके अलावा ईरान से 7-8 लाख टन चीनी की फ्रेश डिमांड है। इसलिए मौजूदा कारोबारी हालात में 45 लाख टन चीनी निर्यात कोई बड़ी बात नहीं है।' पिछले साल सरकार ने मिलर्स से 50 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए कहा था, लेकिन 37 लाख टन ही कर पाए थे। एक व्यापार अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'इस साल मिल मालिकों को इंडोनेशिया से डिमांड की उम्मीद है। वह भारत को ज्यादा पाम ऑयल बेचना चाहता है, जिसके बदले उसने चीनी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इंडोनेशिया अमूमन थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया से चीनी खरीदता है। अगर वह भारत से खरीदारी करता है तो 60 लाख टन का लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकता है।'

इस साल चीनी का उत्पादन 2.6 करोड़ टन रह सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले 21.5 प्रतिशत कम है। यह प्रॉडक्शन घरेलू मांग पूरा करने भर का ही है। हालांकि, पिछले साल के 1.45 करोड़ टन के स्टॉक की मदद से मिलर्स आक्रामक तरीके से निर्यात कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट टारगेट हासिल कर लिया जाता है तो भी 90 लाख टन का सरप्लस स्टॉक बचेगा।

26/12/19